Committee will decide the quantum of additional assistance from National Fund for Calamity Relief based on the report of the Team.

सूखे एवं बाढ़ के कारण होने वाली क्षति

313. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान किन-किन राज्यों की फसलों को सूखे एवं बाढ़ के कारण क्षति पहुंची;

(ख) इस क्षति का राज्य-वार आकलन कितना-कितना है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों को ऋण एवं अनुदान के रूप में प्रदान की गई सहायता की धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्य सरकारों द्वारा वास्तव में क्रमशः ऋण तथा अनुदान के रूप में कितनी-कितनी धनराशि की मांग की गई थी; और

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कौन-कौन से जिलों को सूखा ग्रस्त क्षेत्र मानकर उन्हें कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई और इन राज्यों के किसानों को प्रदान की गई अन्य राहतों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) से (घ) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, बाढ़ों और सूखे के कारण विभिन्न राज्यों में, 1996-97 के दौरान फसलों को हुए नुकसान की प्रमात्रा, आपदा राहत निधि से जारी की गई निधियों, राहत उपायों के लिए मांगी गई अतिरिक्त सहायता तथा राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से दी गई अतिरिक्त सहायता का ब्यौरा प्रदर्शित करने वाला एक विवरण दिया गया है। **(नीचे देखिए)** राहत उपायों के लिए ऋण सहायता हेतु कोई अनुरोध किसी भी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया था कि 9 जिले अर्थात बालाघाट, रायपुर, दुर्ग, सिवनी, राजगढ़, राजनन्दगांव, झबुआ, जबलपुर और रायगढ़ 1996-97 के दौरान भिन्न-भिन्न मात्रा में सूखे की स्थितियों से प्रभावित थे। प्रभावित जिलों में किसानों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए राहत उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—(1) सिंचाई तथा पशुओं के प्रयोजनों के लिए बहते पानी के संरक्षण के लिए बहते नालों तथा छोटी रेवुलेटों के किनारों पर कच्चे बांधों का निर्माण (2) छोटे तथा मार्जिनल किसानों को बीजों का संवितरण (3) सरकारी तथा सहकारी देय राशि की वसूली तथा भू- राजस्व के संग्रहण का आस्थगन और (4) जरुरतमंद किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन कार्यक्रम। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इन जिलों में 56.53 करोड़ रुपए की राशि सूखा राहत उपायों पर खर्च की गई है।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र०स०	राज्य	प्रभावित बोया गया क्षेत्र (लाख है० में)		आपदा राहत कोष (सी०आर० एफ०) से निर्मुक्त की गई राशि	मांगी गई अतिरिक्त सहायता	राष्ट्रीय आपदा आपदा राहत कोष (एन०एफ० सी०आर०) से निर्मुक्त की गई राशि
		बाढ़	सूखा			
1.	आंध्र प्रदेश	22.63		93.14	2819.37	142.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.06		5.28	110.53	3.00
3.	असम	2.46		37.51	415.91	21.00
4.	बिहार	7.34		38.97	168.92	7.00
5.	गुजरात	4.28	3.75	104.70	497.78	—
6.	हरियाणा	0.23		18.79	145.36	—
7.	हिमाचल प्रदेश	4.58		20.21	458.37	10.56
8.	जम्मू एवं कश्मीर	0.46		14.78	273.97	—

(करोड़ रुपए में)

क्र॰सं॰	राज्य	प्रभावित फ़ैला गया क्षेत्र (लाख है॰ में)		आपदा राहत कोष (सी॰आर॰ एफ॰) से निर्मुक्त की गई राशि	मांगी गई अतिरिक्त सहायता	राष्ट्रीय आपदा आपदा राहत कोष (एन॰एफ॰ सी॰आर॰) से निर्मुक्त की गई राशि
		बाढ़	सूखा			
9.	कर्नाटक	0.83		31.39	621.55	—
10.	केरल	0.39		41.55	342.00	—
11.	मध्य प्रदेश	2.63	8.48	38.31	256.19	—
12.	महाराष्ट्र	—	3.80	51.15	—	—
13.	उड़ीसा	0.20	20.53	36.76	570.70	54.00
14.	राजस्थान	2.10		134.28	321.00	—
15.	तमिलनाडु	3.28		44.51	621.55	25.00
16.	उत्तर प्रदेश	6.78		93.84	589.90	—
17.	पश्चिम बंगाल	0.83		38.49	309.00	—
	कुल	57.08	36.56	843.66	8522.10	262.56

Area under Sugarcane Crop

314. SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the reasons for contraction in the area under sugarcane crop;

(b) the extent of the area that has passed from sugarcane cultivation to other crops; and

(c) whether this trend is likely to adversely affect the production of sugar in the country and steps being taken to reverse the trend?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) there has generally been a rising trend in the area under sugarcane since mid eighties. It reached a record level of 41.39 lakh hectares during 1995-96. However, during the year 1996-97, the area marginally declined to 40.49 lakh hectares which is attributed to cyclical flutuations and prolonged crushing during the last season resulting in non-release of land for cultivation of sugarcane in the subsequent year.

(c) No, Sir. in order to increase the productivity and production of sugarcane, a Centrally Sponsored Scheme on sustainable Development of Sugarcane Based Cropping System Areas (SUBACS) has been initiated from the year 1995-96 in 21 States.

Research Programme in Sugarcane

315. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme with regard to research programme in sugarcane in Punjab and Uttar Pradesh for improving technology and varieties of sugarcane;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) Yes, Sir.

(b) All India Coordinated Reasearch Project on Sugarcane is in operation at Jalandhar and Feridkot it Punjab and at